पेज थ्री देहरादून

हमारा दून

देहरादून, बृहस्पतिवार, 24 फरवरी 2022 पेज 8

39 वर्ष बाद द्योनाई घाटी में अबीर–गुलाल उड़ेगा।

राज्य के बालगृह को हैप्पी होम बनाया जाएगा

■ दूरस्थ गांव से जुड़कर आयोग शिकायतों का निस्तारण और उनकी डिजिटल काउंसलिंग करेगा

■ बाल मित्र थाने की कार्रवाई पूरी करने समेत 12 बिंदुओं पर सहमति बनी

सहमति

संवाददाता

देहरादून। बच्चों को मानसिक तौर पर मजबूत करने और पढ़ाई के साथ विभिन्न गतिविधियों में शामिल करने के लिए राज्य के बालगृह को हैप्पी होम बनाया जाएगा। इसके अलावा जिले के दूरस्थ गांव से जुड़कर आयोग शिकायतों का निस्तारण और उनकी डिजिटल काउंसलिंग करेगा। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बोर्ड बैठक में नशे में लिप्त बच्चों को बाहर लाने, आरटीई के तहत गुणवत्ता परक शिक्षा देने, आयोग को डिजिटल दिशा में कार्य करने, बालगृहों को हैप्पी होम बनाने और प्रत्येक जिले में बाल मित्र थाने की कार्रवाई पूरी करने समेत 12 बिंदुओं पर सहमति बनी।

बैठक में कुल 32 प्रस्ताव हुए पासः नंदा की चौकी स्थित उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सभागार में अध्यक्ष डा. गीता खन्ना की अध्यक्षता में कार्यकाल की प्रथम बोर्ड बैठक हुई। जिसमें सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक में कुल 32 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें से 12 पर सहमति बनी। नौ प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने, जबकि दो प्रस्ताव विचाराधीन रहे। सभी ने बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति गंभीरता से कार्य करने पर जोर दिया। आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना ने कहा कि उत्तराखंड में बच्चे किसी न किसी रूप में नशे में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत स्कूलों में बच्चों को दाखिला देने के लिए बस्तियों में भी अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। कहा कि आयोग में किसी भी तरह की शिकायत, काउंसलिंग के लिए डिजिटल करने की तैयारी की जा रही है। जिससे जिलों के दूरस्थ गांव में बैठे व्यक्ति को आयोग से आसानी से जुडने में मदद मिलेगी।

डाक्यूमेंट्री फिल्म बनाएगा आयोग साथ ही आयोग डाक्यूमेंट्री फिल्म बनाएगा, जिससे लोग आयोग में अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो सकेंगे। कहा कि कार्यशैली की सुधार की दशा में बदलाव करते हुए एडवाइजरी पर कार्य किया जाएगा। बैठक में बच्चों की पढ़ाई के साथ ही कलात्मक प्रतिभा को निखारने पर भी जोर दिया गया। इसके लिए राज्य के सभी बालगृहों को हैप्पी होम बनाने पर सहमति बनी।

बैठक में आयोग के ढांचे का पुनर्गठन पर आयोग की कार्यप्रणाली को गति दिलाने के लिए कार्मिकों की कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए कुछ पदों पर नियुक्ति पर भी सहमति बनी। सभी जिलों में समय सीमा के तहत बाल मित्र पुलिस थाना बनाने, बच्चों में सृजनात्मक और कलात्मक प्रतिभा को उभारने केलिए वातावरण बनाने, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जोड़ने, बच्चों में हिंसा की जगह रचनात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में आयोग के सचिव आलोक कुमार पांडेय, वित्त नियंत्रक हर सिंह बोनाल, सदस्य दीपक गुलाटी, रेखा रौतेला, विनोद कपरवाण, अजय वर्मा, सुमन राय, धर्म सिंह आदि मौजूद रहे।

जागरूक और रेस्क्यू करने का होगा कार्य

आयोग के सदस्य स्कूल प्रबंधक, पुलिस प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से इन्हें जागरूक और रेस्क्यू करने का कार्य करेगा।

थाना, चौकियों व फायर स्टेशन के नए भवन के लिए मिली मंजूरी

मंजूरी

■ उत्तराखंड में 120 करोड़ से बनेंगे नए थाना, चौकी और फायर स्टेशन भवन

संवाददाता

देहरादून। प्रदेश के आठ जिलों में खस्ताहाल या दूसरे विभागों के भवन में चल रहे 12 थाना, 25 पुलिस चौकियों व छह फायर स्टेशन को जल्द नए भवन मिलेंगे। संभवतः मई महीने से नए भवनों का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। इस पर कुल 120 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

पुलिस मुख्यालय में लंबे समय से खस्ताहाल थाना, चौकियों और फायर स्टेशन को अपग्रेड करने का मामला चल रहा था। इसके लिए कई बार शासन में प्रस्ताव भी भेजे गए, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हो पाए। अब थाना, चौकियों व फायर स्टेशन के नए भवन के लिए शासन की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

पुलिस लाइन का भी होगा सुधारीकरणः विभाग की ओर से पहले फेज में छह जिलों की पुलिस लाइन के सुधारीकरण का भी प्रस्ताव बनाया गया है। इनमें पुलिस लाइन अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और चमोली शामिल हैं।

विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिला प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें इन जिलों की पुलिस लाइनों की हालत खस्ता पाई है। केवल खुराना (आइजी पुलिस मार्डनाइजेशन, पुलिस मुख्यालय) ने कहा कि प्रदेश में कई थाना, पुलिस चौकी व फायर स्टेशन दूसरे विभागों की बिल्डिंग पर चल रहे हैं। इसके साथ कुछ बिल्डिंग खस्ताहाल हैं।

नई बिल्डिंग के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। करीब 120 करोड़ रुपये से थाना, चौकियों व फायर स्टेशन की बिल्डिंग तैयार की जाएंगी।

इन जिलों में बनेंगे नए भवन

- हरिद्वारः सिडकुल व कलियर शरीफ
- रुद्रप्रयागः सोनप्रयाग थाना
- नैनीतालः बेतालघाट
- पिथौरागढ़ः गंगोलीहाट, जाजर देवल व गुंजी
- चमोलीः गैरसैंण
- उधमसिंहनगरः पुलभट्टा व ट्रांजिट कैंप
- बागेश्वरः कांडा
- टिहरीः लंबगांव

इन जिलों में बनेंगे फायर स्टेशन

- उत्तरकाशी जिले में पुरोला
- अल्मोड़ा में सल्ट, जैंती व द्वाराहाट
- उधमसिंह नगर में किच्छा
- चंपावत हेडक्वार्टर

संक्षिप्त समाचार

सुधोवाला के जंगल में छात्र का शव मिलने से हड़कंप

संवाददाता देहरादून। देहरादून में सुधोवाला के पास जंगल में छात्र का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है। मृतक छात्र बरेली निवासी बताया जा रहा है। छात्र बाबा फरीद इंस्टीट्यूट में बीएससी बायोटेक थर्ड ईयर में अध्ययनरत था। 23 वर्षीय छात्र की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने स्वजन को सूचित कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

यूक्रेन से हमारे बच्चों को सुरक्षित वापस लाए सरकार

संवाददाता देहरादून। रूस के तल्ख तेवर और यूक्रेन में उपजे संकट के बीच युद्ध के आसार बन गए हैं। ऐसे में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत लिवीव, खारकीव जैसे शहरों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए देहरादून से गए छात्र और छात्राओं के परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। परिजन चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे उनके बच्चों को भारत सुरक्षित लाया जाए। इसके लिए अभिभावकों ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से गुहार भी लगाई है। हाथीबड़कला केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका रश्मि बिष्ट का बेटा सूर्यांश सिंह बिष्ट यूक्रेन के लिवीव मेडिकल कालेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की खबरें मीडिया में आने के बाद रश्मि को बेटे की चिंता सताने लगी है।

जैव चिकित्सा विज्ञान का प्रौद्योगिकीकरण समय की मांग

संवाददाता देहरादून। पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पद्मश्री प्रो. आरसी सोबती ने कहा कि जैव चिकित्सा विज्ञान का प्रौद्योगिकीकरण समय की मांग है। जीन एडिटिंग, जैव विविधता, पारंपरिक पद्धतियां और विज्ञान के अध्ययन से जुड़े छात्र–छात्राएं, शिक्षक व शोधार्थी विज्ञान के विकास को मानवीय हितों से जोड़ें। मंगलवार से उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकास्ट) विज्ञानधाम में साप्ताहिक विज्ञान महोत्सव शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रो. आरसी सोबती ने छात्र–छात्राओं व विज्ञानियों को संबोधित किया।

कूड़ा उठाने वाली कंपनी का ही गंदगी फैलाने पर काटा चालान

संवाददाता देहरादून। शहर में डोर–टू–डोर सफाई व्यवस्था व कूड़ा उठान की व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। हालात ऐसे हैं कि एक तरफ नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण–2022 की तैयारी का पुख्ता दावा कर रहा, दूसरी तरफ शहर से कूड़ा उठान करने वाली चेन्नई एमएसडब्ल्यू कंपनी की मनमानी जारी है। वार्डों में हफ्ते–हफ्ते तक कूड़ा उठान नहीं हो रहा। गाड़ियां नहीं आ रहीं। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने इस संबंध में चेन्नई एमएसडब्ल्यू कंपनी का ही गंदगी फैलाने पर चालान काट दिया।

पांच साल में 158 बिल जमा केंद्र नहीं बना पाया यूपीसीएल

संवाददाता देहरादून। 447 करोड़ से अधिक के घाटे से जूझ रहा उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) अपने ही बिजली बिलों की वसूली के लिए बिल जमा केंद्र नहीं बना पा रहा है। पांच साल से चल रही इस प्रक्रिया पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल को कड़ी फटकार लगाते हुए 31 जुलाई तक हर हाल में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2017 में यूपीसीएल ने नियामक आयोग के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि प्रदेश में राजस्व वसूली का लक्ष्य हासिल करने के लिए 11 करोड़ 20 लाख रुपये कीमत से 158 बिल जमा केंद्र बनाए जाएंगे। इस प्रस्ताव को नियामक आयोग ने हरी झंडी दे दी थी। जिसके बाद इन बिल जमा केंद्रों का काम शुरू हुआ, लेकिन कुमाऊं में 28 केंद्रों पर काम शुरू होने के साथ ही ठेकेदार पीछे हट गए।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिंटर्स,74/9,आराघर,देहरादून से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।

(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।